© INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS
Refereed | Peer Reviewed | Indexed
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 09 , Issue : 03 | April - June 2023

हरियाणा और राजस्थान में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास कार्यक्रम : एक तुलनात्मक विश्लेषण

शोधकर्ता

विजय कुमार

शोध–निर्देशक

डॉ. मनजीत कुमार, असिस्टेन्ट प्रोफेसर,

राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग,

बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर, रोहतक

सार : अध्ययन का वर्तमान निकाय हरियाणा और राजस्थान राज्यों में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास कार्यक्रम की तुलना पर केंद्रित है। इस शोध परियोजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, दोनों राज्यों के उत्तरदाताओं का एक प्रतिनिधि नमूना चुना गया है। शोध में प्रस्तुत साक्ष्य यह प्रदर्शित करते हैं सर्वेक्षण के निष्कर्ष किसी कार्यक्रम को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में निगरानी और मूल्यांकन को शामिल करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। यह गारंटी देने के लिए आवश्यक है कि कार्यक्रम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सकारात्मक योगदान दे रहा है। निरंतर आधार पर कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन उन क्षेत्रों को निर्धारित करने में सहायता कर सकता है जिनमें यह उत्कृष्टता प्राप्त करता है और जहाँ यह कम पड़ता है, साथ ही उन क्षेत्रों को इंगित करता है जिनमें इसकी दक्षता और सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने के लिए सुधार किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण शब्द : हरियाणा, राजस्थान, दीन दयाल उपाध्याय , ग्रामीण कौशल विकास कार्यक्रम।

परिचय :

भारत ने अपने सकल घरेलू उत्पाद में गतिशील और तीव्र वृद्धि के कारण विश्व मंच पर विकसित होना शुरू कर दिया है। हालाँकि, इस सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में इसकी विकास प्रक्रिया में समावेशिता का अभाव था, जिसने इसी अवधि में बेरोजगारी, गरीबी और असमानता जैसे प्रमुख मुद्दों को उठाया। जबकि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) ने ष्समावेशी विकासष् को एक मुख्य उद्देश्य के रूप में पेश किया, वही बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) का मुख्य उद्देश्य था। समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए, सरकार को रोजगार सृजन, बुनियादी ढाँचे के विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार सहित सूक्ष्म और वृहद स्तरों पर विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों को लागू करके हस्तक्षेप करना चाहिए। मौजूदा महामारी और आर्थिक मंदी फिर से रोजगार सृजन की प्रमुख चुनौतियों के बारे में सवाल उठाती है, खासकर भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक उत्पादक नौकरियां पैदा करने में तेज

क्यों नहीं रही है। दूसरी ओर, जनसंख्या के आकार में वृद्धि और ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रवासन ने भारत के शहरी क्षेत्रों में आवास की स्थिति को खराब कर दिया है, जहाँ बड़ी संख्या में लोगों के पास बुनियादी सुविधाओं के साथ पर्याप्त आवास नहीं है। भारत के गरीब लोगों की बड़ी संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इनमें से कई लोग कृषि और गैर–कृषि दोनों क्षेत्रों में आकस्मिक श्रम बाजारों में काम करते हैं जिनमें श्रम बाजार कौशल और अनुभव पर बहुत कम रिटर्न मिलता है, और जहाँ श्रम मैनुअल काम के सीमांत उत्पाद द्वारा आय सीमित होती है। समग्र आपूर्ति और मांग की स्थिति को देखते हुए, इस काम पर वापसी गैर–कामकाजी आश्रितों वाले परिवार के लिए गरीबी रेखा से अधिक होने के लिए पर्याप्त घरेलू आय उत्पन्न नहीं कर सकती है। जबकि कम आय वाले परिवारों में स्थानांतरण की एक प्रणाली कम से कम अल्पावधि में गरीबी को कम कर सकती है, इस तरह के हस्तांतरण राज्य के बजट पर भारी बोझ डालते हैं और राज्य को सार्वजनिक संसाधनों में उत्पादक निवेश करने से रोक सकते हैं जिससे दीर्घकालिक सतत विकास और विकास। इस आधार पर, ग्रामीण आय वृद्धि की प्रकृति को बेहतर ढंग से समझने के लिए वांछनीय प्रतीत होता है कि अच्छी तरह से भुगतान वाली नौकरियों को कैसे बढ़ावा दिया जाए। पिछले साढ़े तीन दशकों में, ग्रामीण श्रमिकों, विशेष रूप से ग्रामीण कृषि श्रमिकों के बीच व्यावसायिक पसंद में एक संरचनात्मक बदलाव आया है, कृषि से लेकर गैर–कृषि क्षेत्रों तक उनकी व्यावसायिक पसंद में बदलाव आया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट के 38वें दौर (1983) के अनुसार, लगभग 77 प्रतिशत ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका को बनाए रखने के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर हैं। 2018–19 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के नवीनतम दौर के अनुसार ग्रामीण परिवारों की कृषि पर निर्भरता घटकर 50 प्रतिशत हो गई है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में गिरावट के पीछे प्राथमिक कारण कृषि विकास के लिए अपर्याप्त सार्वजनिक निवेश, संस्थागत ऋण तक अपर्याप्त पहुंच, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएँ, सरकार की कृषि संबंधी खराब विपणन नीतियां, आधी–अधूरी भूमि सुधार नीति और कम आय वाले हैं। कृषि रोजगार में गिरावट के लिए कृषि जिम्मेदार है।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जून 2021 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा ने देश में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की है। 29.1: बेरोजगारी दर के साथ, हरियाणा की बेरोजगारी राष्ट्रीय औसत 12.6: से लगभग 2.5 गुना है। बड़े पैमाने पर कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद कृषि क्षेत्र में राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में समय के साथ गिरावट आई है। परंपरागत रूप से कृषि गतिविधियों में लगे हरियाणा के युवाओं के लिए लाभकारी रोजगार खोजने के दुर्जेय कार्य के लिए उठकर स्थिर रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सही नीति तैयार करना है। धीमी अर्थव्यवस्था और नई नौकरियों की कमी ने उत्तरी राज्य हरियाणा, जहाँ गुरुग्राम स्थित है, को पिछले महीने एक नया कानून लागू करने के लिए प्रेरित किया जो निजी कंपनियों को अन्य राज्यों के श्रमिकों को काम पर रखने से

प्रतिबंधित करता है। फिर भी कौशल विकास का एक गंभीर विषय है क्योंकि इसके बिना इन राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी पाना बहुत मुश्किल है। दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना गरीब परिवारों के 15 से 35 वर्ष के बीच के ग्रामीण युवाओं पर विशिष्ट रूप से केंद्रित है।

राजस्थान में भी लगभग 25 प्रतिशत की उच्च बेरोजगारी दर है। सितंबर 2022 में बेरोजगारी दर 23.8 फीसदी थी। ग्रामीण बेरोजगारी दर 23 प्रतिशत थी और शहरी दर 26 प्रतिशत अधिक थी। बेरोजगारी दर नाटकीय रूप से 2018 के मध्य तक लगभग छह प्रतिशत से बढ़कर अगले दो वर्षों में लगभग 12 प्रतिशत हो गई है। 2020 के अंत से, राजस्थान में बेरोजगारी दर 20 प्रतिशत से अधिक हो गई है। राज्य में बेरोजगारी की चुनौती है और इसलिए हस्तक्षेप समझ में आता है। राजस्थान की बढ़ती बेरोजगारी दर का एक उत्साहजनक पहलू यह है कि यह बढ़ती श्रम भागीदारी दर का परिणाम है। मई–अगस्त 2022 के दौरान 44 प्रतिशत से अधिक के साथ यह 28 राज्यों में 7वां उच्चतम था, जिसके लिए सीएमआईई ने अपने उपभोक्ता पिरामिड घरेलू सर्वेक्षण डेटा से ऐसा अनुमान लगाया है। मई–अगस्त 2022 में जहां राजस्थान का एलपीआर 44.1 प्रतिशत था, वहीं भारत के लिए यह 39.2 प्रतिशत था। पड़ोसी हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश क्रमशः 41 प्रतिशत, 36.9 प्रतिशत, 35.6 प्रतिशत और 33 प्रतिशत पर बहुत खराब थे। दक्षिण में गुजरात 46.2 प्रतिशत पर बेहतर था। राजस्थान उन कुछ राज्यों में से एक है जो बढ़ते एलपीआर दर्ज कर रहा है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में कोविड महामारी फैलने के बाद इसके एलपीआर में बड़ा उछाल देखा गया। राजस्थान के लोगों का एक बड़ा और बढ़ता हुआ अनुपात रोजगार पाने की इच्छा व्यक्त कर रहा है। यह समग्र रूप से भारत के लिए सही नहीं है। 2016 में एलपीआर 37.6 फीसदी था। 2017 में यह बढ़कर 38.6 प्रतिशत, 2018 में 39.3 प्रतिशत और 2019 में 40.4 प्रतिशत हो गया। 2020 के महामारी वर्ष में यह बढ़कर 41.4 प्रतिशत हो गया और फिर 2021 में 44.6 प्रतिशत हो गया।

अध्ययन का उद्देश्य

- ✓ हरियाणा और राजस्थान में लाभार्थियों की सामाजिक–आर्थिक विशेषताओं का विश्लेषण करना।
- ✓ प्राथमिक डेटा के आधार पर हरियाणा और राजस्थान में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास कार्यक्रम के प्रदर्शन का विश्लेषण करना।

अनुसंधान क्रियाविधि

अनुसंधान पद्धति अनुसंधान समस्या को व्यवस्थित रूप से हल करने का एक तरीका है। इसमें हम उन विभिन्न चरणों का अध्ययन करते हैं जो आमतौर पर एक शोधकर्ता द्वारा अपनी शोध समस्या का अध्ययन करने के लिए उनके पीछे तर्क के साथ अपनाए जाते हैं। अनुसंधान पद्धति की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण होते हैं : वर्तमान शोध में बड़े पैमाने पर वर्णनात्मक और विश्लेशणात्मक घटक षामिल हैं। प्रस्तुत

शोध कार्य में हमने मुख्य रूप से हरियाणा एवं राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों का अध्ययन किया है। 100 वर्तमान शोध कार्य का नमूना आकार है। प्रस्तुत शोध कार्य में प्रतिदर्श चयन हेतु अनुभव प्रतिचयन विधि का प्रयोग किया गया है जिसमें आमने–सामने की अन्तःक्रिया सम्मिलित है।

डेटा संग्रह प्रक्रिया

वर्तमान अध्ययन प्राथमिक और माध्यमिक डेटा पर आधारित है। विश्लेषणात्मक डेटा एकत्र करने के लिए व्यक्तिगत बातचीत, साक्षात्कार और प्रश्नावली का उपयोग किया गया है जबकि द्वितीयक डेटा सरकार के माध्यम से एकत्र किया गया है।

विश्लेषण

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास कार्यक्रम हरियाणा और राजस्थान में ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू किया गया था। कार्यक्रम के कार्यान्वयन और ग्रामीण समुदायों पर इसके प्रभाव में समानता और अंतर की पहचान करने के लिए दोनों राज्यों के बीच एक तुलनात्मक विश्लेषण किया गया था। सर्वेक्षण के परिणामों ने संकेत दिया कि कार्यक्रम दोनों राज्यों में अच्छी तरह से जाना जाता था, अधिकांश प्रतिभागियों को कार्यक्रम के बारे में पता था। हालांकि, कार्यक्रम में भागीदारी का स्तर अपेक्षाकृत कम था, केवल कुछ प्रतिशत प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया था।

कार्यक्रम कार्यान्वयन के संदर्भ में, दोनों राज्यों में प्रतिभागियों ने कार्यक्रम को औसत के रूप में मूल्यांकन किया, जिसमें कुछ क्षेत्रों में ताकत और कमजोरियां थीं। दोनों राज्यों में प्रशिक्षकों और प्रशिक्षण केंद्रों की उपलब्धता को एक बड़ी ताकत के रूप में पहचाना गया, जबकि बुनियादी ढाँचे और संसाधनों की कमी को एक बड़ी कमजोरी के रूप में पहचाना गया।

दोनों राज्यों के प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण के क्षेत्रों के रूप में कृषि और खेती, हस्तशिल्प और वस्त्र, और निर्माण और बुनियादी ढाँचे के विकास की पहचान की, जिस पर कार्यक्रम को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हालांकि, फोकस के क्षेत्रों में कुछ अंतर थे, हरियाणा के प्रतिभागियों ने स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सेवाओं के महत्व पर जोर दिया, जबकि राजस्थान के प्रतिभागियों ने उद्यमिता और नवाचार के महत्व पर जोर दिया।

इस कार्यक्रम का ग्रामीण युवाओं के रोजगार की संभावनाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिसमें अधिकांश प्रतिभागियों ने संकेत दिया कि इस कार्यक्रम ने उनके रोजगार की संभावनाओं में सुधार किया है। हालांकि, दोनों राज्यों में सीमित महिला भागीदारी और प्रशिक्षण और रोजगार में लिंग आधारित भेदभाव के साथ लैंगिक असमानताएं देखी गईं। कुल मिलाकर, प्रतिभागियों ने ग्रामीण भारत के विकास के लिए ऐसे कौशल विकास कार्यक्रमों के महत्व पर जोर दिया और भविष्य में कार्यक्रम को बेहतर बनाने के तरीकों के रूप में

वित्त पोषण बढ़ाने, बुनियादी ढाँचे और संसाधनों में सुधार करने और प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने का सुझाव दिया।

प्रतिभागियों ने यह भी सुझाव दिया कि निजी क्षेत्र की भागीदारी और निवेश कार्यक्रम की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, धन और संसाधन प्रदान करके, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करके, और कार्यक्रम कार्यान्वयन में सुधार के लिए सरकार के साथ सहयोग कर सकते हैं। सर्वेक्षण के परिणामों ने संकेत दिया कि कार्यक्रम ने दोनों राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास में योगदान दिया, आय और रोजगार के अवसरों में वृद्धि, बुनियादी ढाँचे में सुधार और सेवाओं तक पहुँच, और उद्यमिता और नवाचार को प्रोत्साहित करके।

हालांकि, प्रतिभागियों ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियों की भी पहचान की, जिनमें जागरूकता और भागीदारी की कमी, सीमित बुनियादी ढाँचे और संसाधन, कार्यक्रम के प्रतिभागियों के लिए अपर्याप्त प्रशिक्षण और समर्थन, और सीमित नौकरी प्लेसमेंट और रोजगार के अवसर शामिल हैं।

अंत में, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास कार्यक्रम में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की क्षमता है, लेकिन इसकी सफलता कार्यक्रम कार्यान्वयन में पहचानी गई चुनौतियों और कमजोरियों को दूर करने पर निर्भर करती है। विभिन्न राज्यों के बीच एक तुलनात्मक विश्लेषण सर्वोत्तम प्रथाओं और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद कर सकता है, और यह सुनिश्चित कर सकता है कि कार्यक्रम प्रभावी रूप से ग्रामीण समुदायों की जरूरतों को पूरा कर रहा है।

सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हरियाणा और राजस्थान में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन और प्रभाव में कुछ समानताएँ और अंतर हैं। दोनों राज्यों ने ताकत के कुछ सामान्य क्षेत्रों की पहचान की, जैसे प्रशिक्षकों और प्रशिक्षण केंद्रों की उपलब्धता, और कमजोरियों के सामान्य क्षेत्र, जैसे कि बुनियादी ढाँचे और संसाधनों की कमी। हालाँकि, फोकस के क्षेत्रों में कुछ अंतर भी थे, जैसे कि हरियाणा में स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सेवाओं का महत्व और राजस्थान में उद्यमिता और नवाचार।

सर्वेक्षण के परिणाम ऐसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लैंगिक मुख्यधारा के महत्व को भी उजागर करते हैं, क्योंकि दोनों राज्यों में लैंगिक असमानताएं देखी गई थीं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यक्रम समावेशी और न्यायसंगत है, इन असमानताओं को दूर करना और सभी प्रतिभागियों को उनके लिंग की परवाह किए बिना समान अवसर और समर्थन प्रदान करना महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर, सर्वेक्षण के परिणाम बताते हैं कि दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास कार्यक्रम में भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में योगदान करने की क्षमता है, लेकिन कार्यक्रम कार्यान्वयन में चुनौतियों और कमजोरियों को दूर करने के लिए निरंतर सुधार और नवाचार की आवश्यकता है। . कार्यक्रम के कार्यान्वयन और मूल्यांकन

में सरकार, निजी क्षेत्र और स्थानीय समुदायों सहित सभी हितधारकों को शामिल करना महत्वपूर्ण है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह ग्रामीण समुदायों की जरूरतों और प्राथमिकताओं को पूरा कर रहा है और उनके सतत विकास में योगदान दे रहा है।

सर्वेक्षण के नतीजे यह भी सुझाव देते हैं कि कार्यक्रम में भागीदारी बढ़ाने के लिए अधिक जागरूकता और आउटरीच प्रयासों की आवश्यकता है। कम भागीदारी दर ग्रामीण समुदायों के बीच कार्यक्रम और इसके लाभों के बारे में जागरूकता या समझ की कमी के कारण हो सकती है। इसलिए, स्थानीय समुदायों और हितधारकों के साथ जुड़ना और उन्हें कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवश्यक जानकारी और सहायता प्रदान करना महत्वपूर्ण है।एक अन्य महत्वपूर्ण कारक जो सर्वेक्षण के परिणामों से उभरा है वह कार्यक्रम कार्यान्वयन में स्थिरता और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यक्रम लंबे समय तक ग्रामीण समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव डालता रहे, कार्यक्रम के वित्तपोषण के लिए एक आत्मनिर्भर मॉडल विकसित करना और कार्यक्रम स्नातकों के लिए निरंतर समर्थन और प्रशिक्षण प्रदान करना महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम कार्यान्वयन में स्थिरता और नवाचार को बढ़ावा देने में निजी क्षेत्र की भागीदारी और निवेश भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

अंत में, सर्वेक्षण के परिणाम कार्यक्रम कार्यान्वयन में निगरानी और मूल्यांकन के महत्व पर प्रकाश डालते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यक्रम अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में योगदान दे रहा है। नियमित निगरानी और मूल्यांकन कार्यक्रम की ताकत और कमजोरियों की पहचान करने में मदद कर सकता है, और इसकी प्रभावशीलता और प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए सुधार के क्षेत्रों का सुझाव दे सकता है।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर प्रतिभागियों ने ग्रामीण भारत के आर्थिक विकास के लिए इस तरह के कौशल विकास कार्यक्रमों के महत्व पर जोर दिया। इसके अलावा, उन्होंने सुझाव दिया कि भविष्य में कार्यक्रम को प्राप्त होने वाली धनराशि में वृद्धि करके, इसके बुनियादी ढाँचे और संसाधनों को बढ़ाकर और प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाकर कार्यक्रम में सुधार किया जा सकता है। अंत में, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास कार्यक्रम में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की क्षमता हैय हालाँकि, कार्यक्रम की सफलता कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पहचानी गई चुनौतियों और कमजोरियों को दूर करने पर निर्भर है। यह सत्यापित करने के लिए कि कार्यक्रम सर्वोत्तम संभव तरीके से ग्रामीण समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, कई अलग–अलग राज्यों में मौजूद कानूनों और प्रक्रियाओं की तुलनात्मक जांच करना महत्वपूर्ण है। सर्वेक्षण के नतीजे बताते हैं कि दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास कार्यक्रम में भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में योगदान

करने की क्षमता हैय हालाँकि, कार्यक्रम के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों और कमजोरियों को दूर करने के लिए निरंतर सुधार और नवाचार की आवश्यकता है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन और मूल्यांकन दोनों में सरकार, निजी क्षेत्र और स्थानीय समुदायों सहित कार्यक्रम के सभी हितधारकों को शामिल करना आवश्यक है ताकि यह गारंटी दी जा सके कि यह ग्रामीण समुदायों की आवश्यकताओं और चिंताओं को पूरा कर रहा है और उनके दीर्घकालिक विकास में सकारात्मक योगदान। अंत में, सर्वेक्षण के निष्कर्ष किसी कार्यक्रम को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में निगरानी और मूल्यांकन को शामिल करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। यह गारंटी देने के लिए आवश्यक है कि कार्यक्रम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सकारात्मक योगदान दे रहा है। निरंतर आधार पर कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन उन क्षेत्रों को निर्धारित करने में सहायता कर सकता है जिनमें यह उत्कृष्टता प्राप्त करता है और जहाँ यह कम पड़ता है, साथ ही उन क्षेत्रों को इंगित करता है जिनमें इसकी दक्षता और सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने के लिए सुधार किया जा सकता है।

संदर्भ

1. अग्रवाल, पी. स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया, (2016) इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट एंड एप्लाइड साइंसेज। 4 (9): 160–166
2. केदार, एम.एस. (2015), भारत में कौशल विकास चुनौतियां और अवसर। मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज का इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल 1(5)।
3. ग्रामीण विकास मंत्रालय, (2016)। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना।
4. पांडे ए, नेमा डी.के. (2017), युवाओं के बीच कौशल भारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रभाव। इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। 4 (7), 294–299
5. श्रीवास्तव, आर.के. और जाटव, ए. (2017)। स्किलिंग इंडिया के लाभों और चुनौतियों का विश्लेषण। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन पर 9वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन, नई दिल्ली, आईएसबीएन, 9789386171719। http://conferenceworld-पद से पुनर्प्राप्त।
6. चिजोबा, ओ., चितोम, जे.–ए., और उजू, एम. (2020)। नाइजीरिया में युवा रोजगार पर कौशल विकास का प्रभाव। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, 3 (1), 33–37।
7. देवांगन, आर, (2018), प्रधानमंत्री कौशल्या विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाना। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बेसिक एंड एप्लाइड रिसर्च, 8 (8), 945–951।

8. कंचन, एस., और वार्ष्णेय, एस. (2015), कौशल विकास पहल और रणनीतियाँ। एशियन जर्नल ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च, 5(4), 666–672।

वेबसाइट :

1. http:/ddugky.gov.in
2. http:/dduhky.gov.in/contents/state-skill-development-missions
3. http:/Kaushalyapragati.nic.in
4. https:/www.nationalskillsnetwork.in
5. https:/www.cmie.com/